# अफज़ल गुरु को फांसी देने पर पाकिस्तान की संसद में पारित प्रस्ताव की निंदा करने की मांग

राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कल एक बहुत ही गंभीर घटना हुई। पाकिस्तान कीं संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके एक ऐसे व्यक्ति को फांसी दिये जाने की निंदा की जिसे भारत की संसद पर हमले का दोषी ठहराया गया था। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के अलावा, यह एक आधिकारिक बयान है जो पाकिस्तान की सम्मिलित राजनैतिक व्यवस्था की तरफ से आया है। अभी तक हम लोग यह जानने को उत्सुक थे कि देश में वास्तव में किसका नियंत्रण हैं। उनकी सेना, उनकी आईएसआई, एक नागरिक सरकार या ऐसे संगठन जो देश की आंतरिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। लेकिन कल जो प्रस्ताव पारित किया गया उससे यह उत्सुकता समाप्त हो गई है। यह भारत में हुए सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में से एक को मंजूरी देने की आधिकारिक मोहर है।

अब तक हम हमेशा आरोप लगाते थे और ऐसे सबूत भी हैं जिनसे पता चलता है कि भारत की संसद पर हमले की योजना सीमा पार से बनाई गई थी लेकिन कल का प्रस्ताव हमारी उन आशंकाओं की पुष्टि करता है क्योंकि देश की राजनैतिक व्यवस्था ने इस वारदात में शामिल व्यक्ति को कानून के शासन के जरिये सजा देने की हमारी कार्रवाई की वास्तव में सर्वसम्मति से निंदा कीं। महोदय, हमारे जवानों का सिर धड़ से अलग करने की घटना, हैदराबाद में बम विस्फोट, श्रीनगर में सीआरपीएफ कैम्प पर हमला और अंत में इस तरह का प्रस्ताव पारित करना, स्पष्ट रुप से बताता है कि इस मामले में पाकिस्तान का क्या इरादा क्या हो सकता है। सरकार को अब गंभीरता से इस बारे में विचार करना होगा कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से कैसे निपटा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री पहले उदारतापूर्वक कह चुके हैं कि वह एक अतिरिक्त मील चलने के लिए तैयार हैं।

लगातार उकसावे की ऐसी घटनाओं के बाद, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वे एक अतिरिक्त मील चलने की बात भूल जाएं, उन्हें अब एक अतिरिक्त गज चलने की बात भी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान इस लायक नहीं है। जब तक यह प्रस्ताव रहेगा, पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए जो भारत में आतंकवादी हमले करने वालों के साथ सहानुभूति रखता है। मैं समझता हूं कि हमें उनके साथ किसी भी गंभीर

मसले पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। अतः अब हमारे प्रधानमंत्री के एक अतिरिक्त मील चलने की बजाय पाकिस्तान को दो अतिरिक्त मील चलना होगा। अगर हम संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं तो इस तरह के प्रस्तावों से संबंधों को सामान्य बनाना संभव नहीं होगा। महोदय, यह ऐसी पृष्ठभूमि में आया है जब चाहे माले हो, रोम हो या इस्लामाबाद सभी जगह गंभीर स्थिति है।

मैं समझता हूं कि हमें अपनी विदेश नीति पर गंभीरता से चर्चा करने की जरुरत है और जिस तरफ ये हमें ले जा रही है क्योंकि अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह ठोकर खाता रहेगा, तो इसका मतलब है कि यह एक गंभीर मसला है जिस तरीके से हम अपनी विदेश मामलों को चला रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि एक तारीख तय कीजिए जब माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यहां हों, बयान दें और इस सदन को इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिले।